सोमवार , 02 नवंबर 2026, ठाणे, मुंबई

दैनिक
सिटी न्यूज
सच का जोश
मुंबई

वर्ष - 15 • अंक - 67 CITY NEWS MUMBAI

IIT बॉम्बे छात्र साहिल वाकोड़े केस: माता-पिता ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, CBI जांच की मांग



आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के मामले में माता-पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई या एसआईटी से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। साहिल वाकोड़े के माता-पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सीबीआई या एसआईटी से स्वतंत्र जांच की मांग की। आईआईटी फैकल्टी पर प्रताड़ना और जातिगत टिप्पणी के आरोप लगाए। आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े की मौत के मामले में न्याय की मांग करते हुए उसके ...शेष 7 पर

INDI गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन

वोट चोरी के खिलाफ संग्राम को अब CEC से आगे पीएम मोदी-शाह तक ले जाने की तैयारी में विपक्ष

रामलीला मैदान में INDI गठबंधन ने 'वोट चोरी' के खिलाफ अपनी लड़ाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की कानूनी घेराबंदी का एलान किया। विपक्षी दलों ने रामलीला मैदान की रैली के साथ ही वोट चोरी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के मुद्दे से आगे बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृहमंत्री अमित शाह की राजनीतिक-कानूनी



घेराबंदी करने का एलान कर दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने रैली में दो टूक कहा कि ज्ञानेश कुमार सीइसी पद से हटेंगे और 'देशद्रोह' के मामले में उन्हें जेल भेजा जाएगा। पीएम मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा 'ज्ञानेश कुमार के बाद वोट चोरी मामले में इन दोनों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे कानून से बच सकते हैं।' एसआईआर के जरिए मतदाता सूची से वोटरों को हटाए जाने को देश की आत्मा प्रहार तथा नागरिकों की आवाज दबाने का गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि देश को सही पटरी पर ...शेष 7 पर

भविष्य में आगे क्या होगा कौन जानता है... देवेंद्र-उद्धव मुलाकात पर राउत का बयान

सीएम फडणवीस और ठाकरे बंधुओं की मंच साझीदारी पर संजय राउत ने कहा कि भविष्य में कुछ भी हो सकता है। वहीं मंत्री संजय शिरसाट ने आगामी महीनों में बड़े राजनीतिक बदलाव का दावा किया। फडणवीस और ठाकरे बंधुओं के एक मंच पर आने से सियासी चर्चाएं तेज। संजय राउत ने भविष्य में राजनीतिक बदलाव की संभावना जताई। संजय शिरसाट ने 3-4 महीनों में शिंदे के दोबारा सीएम बनने का दावा किया। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर नए सियासी समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच मतभेदों की खबरों के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। इस घटनाक्रम के बाद शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत के बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को



और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उद्धव और फडणवीस के एक मंच पर आने से चर्चा प्रशांत कुलकर्णी द्वारा संपादित पुस्तक 'महाराष्ट्राच्या हास्यरेषा' के विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग-अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस कार्यक्रम के अगले दिन संजय राउत और भाजपा नेता आशीष शेलार भी एक कार्यक्रम में एक साथ मंच साझा करते नजर आए। राउत ने उद्धव ठाकरे और फडणवीस के एक मंच पर आने को आपसी आत्मीयता का प्रतीक बताया। आशीष शेलार की तारीफ में क्या बोले राउत? शिंदे के दोबारा CM बनने का शिरसाट का दावा दूसरी ओर, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने दावा किया है कि अगले तीन से चार महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। उन्होंने एकनाथ शिंदे के दोबारा मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई। साथ ही कहा कि अगला साल शिवसेना का होगा। भाजपा और शिंदे गुट के बीच विवाद पर भी बयान संजय शिरसाट ने भाजपा और शिवसेना के बीच किसी तरह के विवाद से इनकार किया। हालांकि, उन्होंने भाजपा प्रवक्ता नवनाथ बन को सार्वजनिक बयान देते समय मर्यादा बनाए रखने की सलाह दी। संजय राउत ने लोकतंत्र को बदलाव की प्रक्रिया बताते हुए कहा कि सत्ता में कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं रहता। उन्होंने आशीष शेलार की तारीफ भी की और बदले की राजनीति पर नाराजगी जताई। उनके बयान को महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जा रहा है।

हम रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहे हैं... दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली में संजय राउत का कड़ा हमला



दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली के दौरान संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला। राउत ने कहा कि देश रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहा है और जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली आयोजित हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा देश रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए हुंकार भरी। देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की ओर से आयोजित विशाल 'मेगा रैली' ने देश के राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ ला दिया है। इस भव्य और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान विपक्षी नेताओं के तेवर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। रैली के दौरान शिवसेना (UBT) के ...शेष 7 पर

'सेवा संकल्प अभियान' सफल, हजारों नागरिकों की समस्याओं का एक ही छत के नीचे समाधान

मंत्री प्रताप सरनाईक की पहल से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा, नागरिकों का मिला जबरदस्त प्रतिसाद

मीरा रोड, (सिटी न्यूज़ मुंबई)

महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री एवं धाराशिव जिले के पालकमंत्री प्रताप सरनाईक के मार्गदर्शन में आयोजित 'सेवा संकल्प अभियान' को जबरदस्त सफलता मिली है। इस अभियान के तहत आयोजित तालुकास्तरीय शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों को एक ही छत के नीचे लाकर नागरिकों की समस्याओं के समाधान की पहल की गई। शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। अक्सर आम नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने, योजनाओं का लाभ लेने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने



पड़ते हैं। इसी परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से राजस्व विभाग, भूमि अभिलेख, राशन विभाग, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के स्वास्थ्य एवं समाज विकास विभाग, आरटीओ और सहकारिता विभाग सहित कई सरकारी विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं। शिविर में राजस्व विभाग की ओर से आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, वरिष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र और नॉन-क्रीमीलेयर सहित कुल 110 प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर 7/12 के 8 प्रमाणपत्र, अभियान के



तहत 7/12 के 14 प्रमाणपत्र और वन अधिकार दावों के 7/ई के 39 उतारे वितरित किए गए। इस प्रकार राजस्व विभाग ने कुल 171 नागरिकों को राहत पहुंचाई। भूमि अभिलेख विभाग ने गांवठाण सनद, संपत्ति पत्रिका और क प्रत वितरण से संबंधित 49 मामलों का निपटारा किया। वहीं राशन विभाग ने नए राशन कार्ड और राशन कार्ड में नाम जोड़ने या हटाने से संबंधित 60 आवेदनों का समाधान किया। मीरा-भाईंदर महानगरपालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से जन्म एवं विवाह प्रमाणपत्र, आयुष्मान कार्ड वितरण और स्वास्थ्य जांच शिविर के माध्यम से 49 नागरिकों को लाभ मिला। समाज विकास विभाग ने पीएमएसकेई पहचानपत्र, एसएचजी प्रमाणपत्र और महिला कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित 20 मामलों को पूरा किया। इसके अलावा संपत्ति हस्तांतरण, कर निर्धारण और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को नियमानुकूल करने से संबंधित आवेदनों को भी अच्छा प्रतिसाद मिला। इनमें 140 संपत्ति संबंधी मामले और 140 अतिक्रमण संबंधी आवेदन शामिल हैं। कुल मिलाकर शिविर में 489 मामलों पर कार्रवाई की गई। इस अवसर पर मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि जनसेवा ही ईश्वर सेवा है। सरकार ...शेष 7 पर

रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने क्या-क्या कहा? भाषण की 10 बड़ी बातें

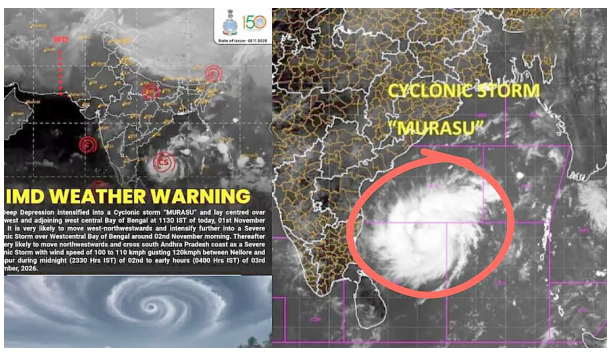
रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए मोदी-शाह और CEC ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की बात कही। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और CEC ज्ञानेश कुमार को संदेश देने की बात कही। उन्होंने कहा कि संविधान सरकार और किसी भी व्यक्ति से बड़ा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में सालों से वोट चोरी हो रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जमकर घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि EVM और वोटर लिस्ट के जरिए चुनावों में गड़बड़ी की गई और 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग करते हुए मोदी-शाह के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। किसानों, युवाओं और मजदूरों का जिक्र करते हुए राहुल ने कहा कि संविधान सबसे ऊपर है और इसे नष्ट नहीं होने दिया जाएगा। आइए जानते हैं राहुल गांधी के भाषण की



10 बड़ी बातें... 1. संविधान बचाने के लिए एकजुट होने की अपील राहुल गांधी ने महारैली में शामिल लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह किसानों, युवाओं और मजदूरों की आवाज है कि वे संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे। 2. मोदी-शाह और ज्ञानेश कुमार को दिया संदेश राहुल गांधी ने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तक अपना संदेश पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान इन सभी से बड़ा है। 3. सालों से हो रही वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में सालों से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि EVM और वोटर लिस्ट के जरिए चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया गया है। 4. 2024 के लोकसभा चुनाव को बताया अवैध राहुल गांधी ने दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव अवैध था। उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से युवाओं के नाम काटे गए और करीब 13 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए। 5. ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की मांग राहुल गांधी ने कहा कि यह कोई सामान्य चोरी नहीं, बल्कि देश के नागरिकों के वोट और उनकी आवाज की चोरी है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जेल भेजने की बात कही। 6. मोदी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर बड़ा दावा राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। 7. मोदी और शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के बाद अब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी खड़े होंगे।

अब अर्नब के बाद मुरासु का खतरा, 2 और 3 नवंबर को इन राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट

अर्नब के बाद आने वाले इस तूफान का नाम 'मुरासु' है जिसका असर देश के कई हिस्सों में पड़ने वाला है। अर्नब के बाद मुरासु चक्रवाती तूफान की दस्तक 2 और 3 नवंबर को कई राज्यों में होगी बारिश ओडिशा, आंध्र प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में अलर्ट भारत पर चक्रवाती तूफान का खतरा मंडरा रहा है। अब 2 और 3 नवंबर को कई राज्यों में बारिश का हाई अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं देश के कई राज्यों में आज भी बारिश की संभावना है। ओडिशा समेत कई राज्यों में आज भारी बारिश की संभावना है। 2 नवंबर को आंध्र प्रदेश की तय से टकराएगा मुरासु अर्नब के बाद आने वाले इस तूफान का नाम मुरासु है। बताया जा रहा है कि मुरासु 2 नवंबर की शाम आंध्र प्रदेश की तट पर पहुंच



जाएगा। इसके असर से आंध्र प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। 2 नवंबर को केरल समेत इन राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट मुरासु चक्रवाती तूफान का खतरा कई राज्यों को है। मौसम विभाग के मुताबिक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। रविवार को कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने साउथ इंडिया के कुछ इलाकों में आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी दी है। मु जानें दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के मुताबिक, मुरासु चक्रवाती तूफान का सीधा प्रभाव राजधानी दिल्ली पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 नवंबर को दिल्ली का अधिकतम तापमान 29C और न्यूनतम तापमान 18C के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में मुख्य रूप से मौसम साफ और धूप खिली रहेगी यानी कि यहां बारिश का कोई खतरा नहीं है। रासु चक्रवाती तूफान की वजह से भारी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक, देश के कई हिस्सों में मुरासु चक्रवाती तूफान का असर कई दिनों तक देखने को मिलेगा। इस दौरान दक्षिण, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश हो सकती है। वहीं कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं। रविवार को अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, केरल और माहे में कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और विदर्भ में भी आंधी-तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है।

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध में चीन से हो रहीं फंडिंग! CM फडणवीस ने राहुल गांधी पर लगाए गंभीर आरोप



CM फडणवीस ने ठाणे रैली में राहुल गांधी और विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के लिए चीन से फंडिंग मिलने का आरोप लगाया है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ठाणे रैली में राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध में चीन से फंडिंग मिलने का दावा किया। फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी चीन के पैसों के दम पर अराजकता फैला रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 1 नवंबर 2026 को ठाणे में आयोजित लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान की विशाल रैली के दौरान विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। ठाणे में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ विपक्ष के आंदोलन का चीन कनेक्शन का दावा किया और चीन से फंडिंग मिलने का सनसनीखेज आरोप लगाया।

पंजाब में AAP को झटका! हरमीत पठानमाजरा और चेतन जौरामाजरा ने छोड़ी पार्टी, दोनों का टिकट कटना था तय



पंजाब में AAP के दो विधायकों हरमीत पठानमाजरा और चेतन सिंह जौरामाजरा के पार्टी से इस्तीफे की खबर है। दोनों के विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी ने पहले ही नए इंचार्ज नियुक्त किए थे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। समाना से विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सनौर के विधायक हरमीत पठानमाजरा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। शनिवार को ही AAP ने पंजाब चुनाव के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इधर आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपने पार्टी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। उधर, दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका लगा है। समाना और सनौर के 2 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सामना से विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।

हम रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहे हैं... दिल्ली में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली में संजय राउत का कड़ा हमला

दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली के दौरान संजय राउत ने केंद्र पर हमला बोला। राउत ने कहा कि देश रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहा है और जनता बदलाव चाहती है। दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की मेगा रैली आयोजित हुई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा देश रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहा है। विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार पर कड़ा हमला बोलते हुए हुंकार भरी। देश की राजधानी दिल्ली स्थित ऐतिहासिक रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक की ओर से आयोजित विशाल 'मेगा रैली' ने देश के राजनीतिक घटनाक्रम में एक नया मोड़ ला दिया है। इस भव्य और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आयोजन के दौरान विपक्षी नेताओं के तेवर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। रैली के दौरान शिवसेना (UBT) के फायरब्रांड सांसद संजय राउत ने मीडिया से



बातचीत करते केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद कड़े और तीखे शब्दों में अपनी बात रखी। संजय राउत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हुंकार भरते हुए कहा, क्रांति आ रही है... क्रांति! हम रिजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं। उनके इस बयान ने दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जनसैलाब और बैरीकेडिंग पर सरकार को चेतावनी राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान रैली में पहुंच रहे जनसैलाब और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में आम नागरिक और कार्यकर्ता दिल्ली की CMO में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को इस रैली में भाग लेने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, संजय राउत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकार और प्रशासन उन्हें रोकने की जितनी अधिक कोशिश करेगा, लोगों का आक्रोश और रैली में आने वाली भीड़ का आकार उतना ही बड़ा और विशाल होता चला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की जनता अब सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है और वह इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करेगी। जनता तमाम सरकारी बैरीकेडिंग और रुकावटों को तोड़ते हुए हर हाल में रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे देश की ताकत रामलीला मैदान से देश को दिए जा रहे संदेश की व्याख्या करते हुए शिवसेना (UBT) सांसद ने कहा कि यह आयोजन महज किसी एक राजनीतिक पार्टी या गठबंधन की ताकत दिखाने का मंच नहीं है।

कभी तालाब था रामलीला मैदान, नेहरू से जेपी और अन्ना आंदोलन तक की कहानी

दिल्ली का रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक राजनीतिक आंदोलनों और रैलियों का गवाह रहा है। जानिए नेहरू, शास्त्री, जेपी, अन्ना हजारे और बाबा रामदेव से जुड़ा इसका इतिहास।

1930 के दशक से पहले रामलीला मैदान की जगह एक बड़ा तालाब हुआ करता था। 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का यहां स्वागत किया था। जेपी आंदोलन, आपातकाल के विरोध और अन्ना हजारे के आंदोलन का भी यह मैदान गवाह रहा है। इं डिया गठबंधन में शामिल विपक्षी दल रविवार (1 नवंबर) को दिल्ली के रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में विपक्षी नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्र संगठनों और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। रैली का उद्देश्य चुनाव में कथित गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताना, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) का विरोध करना और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करना है। इस रैली के लिए विपक्षी दलों ने 'चलो दिल्ली' मार्च का भी आयोजन किया है। मार्च मिंटो रोड से शुरू होकर रामलीला मैदान पहुंचेगा। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी समेत कई विपक्षी नेताओं के शामिल होने की जानकारी है। रामलीला मैदान सिर्फ एक रैली स्थल नहीं है, बल्कि



देश के राजनीतिक इतिहास का अहम गवाह भी रहा है। करीब 12 एकड़ में फैला यह मैदान धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और जन आंदोलनों का केंद्र रहा है। यहां कभी जवाहरलाल नेहरू ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्वागत किया था, तो कभी जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका था। अन्ना हजारे और बाबा रामदेव के आंदोलन भी इसी मैदान से जुड़े रहे हैं। कभी तालाब हुआ करता था रामलीला मैदान दिल्ली का रामलीला मैदान 1930 के दशक से पहले एक बड़ा तालाब हुआ करता था। बाद में इसे पाटकर मैदान में बदल दिया गया। इतिहासकारों के मुताबिक, लाल किले के पीछे यमुना के बाढ़ क्षेत्र में होने वाली रामलीला को यहां स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद यह जगह धार्मिक आयोजनों के साथ-साथ सार्वजनिक सभाओं और राजनीतिक रैलियों का प्रमुख केंद्र बन गई।

नेहरू ने किया था महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का स्वागत रामलीला मैदान ने कई ऐतिहासिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की मेजबानी की है। वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का इसी मैदान में स्वागत किया था। वर्ष 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रामलीला मैदान से 'जय जवान, जय किसान' का नारा दिया था।

राहुल गांधी को कनॉट प्लेस में बंद मिली दुकानें, बोले- कौन करवा रहा व्यापारियों का नुकसान, भाजपा पर लगाए आरोप

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में बीजेपी ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवाईं। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर दावा किया कि कनॉट प्लेस पहुंचने पर उन्हें दुकानें बंद मिलीं। राहुल गांधी ने इसके लिए बीजेपी पर जबरन दुकानें बंद करवाने का आरोप लगाया। व्यापारियों के संगठन CTI ने भी रैली के कारण बाजारों में कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया कि 'INDIA' गठबंधन के मार्च को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कनॉट प्लेस में जबरन दुकानें बंद करवा दीं, जिससे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास से रामलीला मैदान में होने वाले मार्च के लिए कनॉट प्लेस की ओर जाते समय, अपनी गाड़ी से रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में राहुल



गांधी ने कहा कि विपक्षी गठबंधन ने रैली में आने वालों से कनॉट प्लेस में खरीदारी करने के लिए कहा था, ताकि स्थानीय व्यापारियों को फायदा हो सके। भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप राहुल गांधी ने कहा, "लेकिन, कनॉट प्लेस पहुंचने पर पता चला कि BJP ने जबरन सारी दुकानें बंद करवा दी हैं।" कांग्रेस नेता ने BJP पर दुकानदारों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा, "देश देख रहा है कि BJP किस तरह दुकानदारों को नुकसान पहुंचा रही है।" इस आरोप पर अभी तक BJP की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। रा हजारों का कारोबार खतरे में CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने चेतावनी दी है कि लगभग 2.5 लाख दुकानें बंद रह सकती हैं और 10 किलोमीटर के दायरे में परिवहन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं, जिससे 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का कारोबार खतरे में पड़ सकता है। दिल्ली में व्यापारियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से रैली की तारीख आगे बढ़ाने की अपील कर रहा था। लेकिन, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बात नहीं मानी। अब दिवाली के पीक सीजन पर व्यापारियों का बाजार बड़े तौर पर प्रभावित हो रहा है। हुल गांधी ने किया ट्वीट लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, "हमने सबसे कहा था कि जब आप यहां मार्च और मेगा रैली के लिए आएं, तो कुछ चीजें खरीदें, थोड़ी खरीदारी करें। लेकिन, जब हम यहां कनॉट प्लेस पहुंचे, तो पता चला कि बीजेपी ने जबरदस्ती सारी दुकानें बंद करवा दी हैं। इसलिए, आपको पता होना चाहिए कि व्यापारियों का नुकसान कौन करवा रहा है और यह कैसे हो रहा है।" CTI ने राहुल गांधी को दी थी चेतावनी आपको बताते चलें, कि रविवार की सुबह चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चौथा पत्र लिखा था।

श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के 7 मछुआरों को गिरफ्तार किया, मछुआरा संघ ने केंद्र सरकार से दखल की मांग की



श्रीलंकाई नौसेना ने रविवार को सात भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया और उनके ट्रॉलर को जब्त कर लिया। उन पर आरोप है कि वे श्रीलंका के समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। रामेश्वरम के सात मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया मछुआरा संघ ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की अपील की गिरफ्तारी के बात मछुआरा समुदायों में गुस्सा देखा जा रहा है श्रीलंकाई नौसेना ने रामेश्वरम के सात मछुआरों को पकड़ लिया है और मन्नार के पास समुद्र में उनकी मछली पकड़ने वाली नाव को जब्त कर लिया है। इस घटना से मछुआरा समुदाय में काफी रोष है। श्रीलंकाई नौसेना ने इन पर समुद्री सीमा पार करके मछली पकड़ने का आरोप लगाया है और पूछताछ के लिए उन्हें मन्नार नौसैनिक शिविर ले जा रही है। यह घटना शनिवार, 31 अक्टूबर को हुई, जब 'IND TN 10 MM 984' रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक नाव को सात मछुआरों के साथ पकड़ लिया गया।

नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को मिला ग्रीन सिग्नल! सिर्फ साढ़े तीन घंटे में वाराणसी से दिल्ली की यात्रा



सरकार ने बुलेट ट्रेन नेटवर्क के 'उत्तरी कॉरिडोर' को मंजूरी दे दी है। यह दिल्ली से शुरू होकर आगरा, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या को जोड़ेगा और वाराणसी और पटना होते हुए आगे बढ़ेगा। उत्तरी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सरकार ने हरी झंडी दी केंद्रीय रेल मंत्री ने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी वराणासी से दिल्ली की यात्रा में लोगों को कम समय लगेगा केंद्र सरकार ने नए उत्तरी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है, जो उत्तरी भारत में यात्रा के समय को काफी कम करने वाली एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मंजूरी की घोषणा करते हुए बताया कि हाई-स्पीड रेल नेटवर्क प्रमुख शहरों को और करीब लाएगा। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत, यात्री दिल्ली से आगरा की यात्रा मात्र 59 मिनट में कर सकेंगे।

वृंदावन के प्रेमानंद महाराज के बाद Gen Z Baba को मिल रहा लोगों का प्यार; जानिए कौन हैं शाश्वत आचार्य

प्रेमानंद महाराज के बाद अब लोगों ने 'Gen Z Baba'को भी भरपूर प्यार देना शुरू कर दिया है। उनकी रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। Gen Z Baba के नाम से प्रसिद्ध हुए शाश्वत आचार्य शाश्वत आचार्य को लोगों द्वारा भरपूर प्यार मिल रहा मात्र 19 साल की उम्र में बने भागवत कथावाचक साल 2026 खत्म होने के कगार पर है। इस साल Gen Z का ट्रेंड न सिर्फ राजनीति की दिशा में बढ़ा है बल्कि अब Gen Z Baba के नाम से प्रसिद्ध वृंदावन के भागवत कथावाचक श्री स्वामी शाश्वत आचार्य जी महाराज को लोगों द्वारा भरपूर प्यार दिया जा रहा है। इंटाग्राम पर आजकल कब और कौन वायरल हो जाए, नहीं पता। इसी दिशा में 19 साल के शाश्वत आचार्य जी महाराज की रील्स भी वायरल हो रही है। लोग उनकी जिंदगी को जानने के लिए उत्सुक हैं कि वे इतनी कम उम्र में आखिर कथावाचक क्यों



बने? उनकी जिंदगी की कहानी आज हर कोई जानना चाहता है। कौन हैं Gen Z Baba- शाश्वत आचार्य वृंदावन के 19 वर्षीय जेन जी बाबा यानी शाश्वत आचार्य का जन्म एक संत परिवार में हुआ था। उनके पिता वृंदावन आचार्य जी महाराज खुद एक सिद्ध संत हैं। ऐसे में उनके घर में बचपन से ही भजन कीर्तन और शास्त्र अध्ययन का माहौल था। ये बात उस समय की है जब शाश्वत 4 साल के थे। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उन्हें दुनियादारी की समझ नहीं होती। उस उम्र में वे भागवत गीता के श्लोकों का उच्चारण करते थे। कम उम्र में ही उन्होंने मच पर बैठकर छोटी-छोटी कथाएं और प्रवचन देना शुरू कर दिया था। जैसे-जैसे ज्ञान बढ़ता गया, उनकी वाणी में भी मधुरता बढ़ती गई। अब कई लोग उनकी कथा सुनने आते हैं। आज 19 साल की उम्र में वे वृंदावन जिले के एक प्रतिष्ठित मंदिर श्री धाम गोदा विहार मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनका जन्म 5 अगस्त, 2007 को वृंदावन में हुआ था। 'Gen Z Baba'इस विषय की कर रहे पढ़ाई शाश्वत आचार्य के मामा के मुताबिक, फिलहाल वे गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज, मथुरा से बीए-एलएलबी कर रहे हैं। कथावाचन के दौरान वे अपने शांत स्वभाव, कंधे तक घुंघराले बाल, माथे तक चमकता वैष्णव तिलक और चेहरे पर अद्भुत तेज की वजह से जाने जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज के बाद अब 'Gen Z Baba'को मिल रहा प्यार वृंदावन के प्रेमानंद महाराज आज भारत के कोने-कोने में प्रसुद्ध हैं। उनके प्रवचन सुनने बड़े-बड़े सेलिब्रिटी आते हैं। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा आए दिए उनके दरबार में देखे जाते हैं। खास बात अब ये है कि लोगों ने 'Gen Z Baba'को भी भरपूर प्यार दिया है।

सम्पादकीय

प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने का समय

विकसित राजस्थान-2047' के लक्ष्य की दिशा में प्रशासनिक रोडमैप को गति देते हुए राजस्थान के मुख्य सचिव ने बीते दिनों भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी क्यूसीआइ को शासन के छह विभागों के गहन संस्थागत परीक्षण का जिम्मा सौंपा है। इस कवायद का उद्देश्य कार्यप्रणालियों का विस्तृत खाका तैयार करना, विभागीय प्राथमिकताओं के अनुरूप मौजूदा मानव संसाधन की समीक्षा करना, अंतर-विभागीय दोहराव को समाप्त करना और प्रशासनिक पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अरुणाचल प्रदेश भी 2025 में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कर चुका है। केरलम ऐसी चार कवायदें पहले ही पूरी कर चुका है। यह रुझान दर्शाता है राज्यों ने अपनी प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त-दुरुस्त बनाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। जबकि केंद्र सरकार ने 2009 के बाद से ऐसी कोई पहल नहीं की है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत' का नारा तो गढ़ा है, लेकिन वह अपने स्तर पर इस दिशा में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है? कई कसौटियों पर प्रशासनिक सुधार आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य हो गए हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि सरकारी परियोजनाएं भारी लेट-लतीफी की शिकार हैं। केंद्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधिकारिक निगरानी रिपोर्ट दर्शाती है कि 458 परियोजनाओं की स्वीकृत लागत में 5.71 लाख करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो गई है। ये परियोजनाएं कई महीनों से लेकर दशकों की देरी तक खिंच चुकी हैं। सुधारों की राह में इस पहलू को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि सरकारें सबसे बड़ी मुकदमेबाज बन गई हैं। वर्ष 2025 के अंत तक अदालतों में लंबित 5.39 करोड़ मुकदमों में केंद्र और राज्य सरकारें ही एक पक्ष हैं। स्थिति ऐसी बन गई है कि सरकार का एक विभाग ही दूसरे विभाग के खिलाफ अपील दायर कर रहा है और इस तकरार की कीमत आम नागरिकों के लंबित मामलों को चुकानी पड़ रही है। सुधारों की राह में तीसरी कसौटी योजनाओं को सुसंगत बनाने की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का दायरा कागजों पर तर्कसंगत बनाकर 130 से घटाकर 75 मूल श्रेणियों में समेटने का दावा तो किया गया, लेकिन हकीकत यही है कि 2025-26 में इनका बजट 5.4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया। इनमें से तमाम योजनाएं दशकों से चली आ रही हैं, लेकिन उनकी उपयोगिता की व्यापक समीक्षा की सुध पहली बार पिछले साल ली गई है। चौथी कसौटी प्रशासनिक अधिकारियों से ही जुड़ी है। जहां सरकारों के सचिवालय तो बाबुओं से भरे हुए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकारियों का भारी अभाव है। एक जनवरी 2025 तक आइएएस का लगभग हर पांचवां पद और आइएफएस का हर तीसरा पद खाली पड़ा था। इसका असर जिला स्तर और फील्ड पोस्टिंग में स्पष्ट दिखता है। पांचवीं कसौटी यही है कि मौजूदा व्यवस्था में किसी के भी काम की जवाबदेही या प्रदर्शन को समग्रता में नहीं आंका जाता। 'रिजल्ट्स फ्रेमवर्क डाक्युमेंट्स' की व्यवस्था ने एक समय सचिव स्तर के शीर्ष अधिकारियों को वार्षिक लक्ष्यों के लिए सीधे जवाबदेह बनाया था, जिनकी स्वतंत्र समीक्षा तीसरे पक्ष से कराई जाती थी। अपने दौर में करीब 80 विभागों को दायरे में लेने वाली यह व्यवस्था 2013-14 के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई और इसका कोई विकल्प तक तैयार नहीं किया गया। स्पष्ट है कि जो व्यवस्था अपने अधिकारियों की कार्यक्षमता का ही हिसाब नहीं रख सकती तो वह उनके काम की कद्र कर उन्हें पुरस्कृत करेगी? ऐसे में ठोस नतीजों की उम्मीद बेमानी ही कही जाएगी। ऐसा नहीं कि इन विसंगतियों को पहले चिह्नित न किया गया हो। वर्ष 2006 से 2009 के बीच द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के माध्यम से केंद्र सरकार के स्तर पर 15 रिपोर्ट और 1,514 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थीं। इनमें से सरकार ने 1,183 को स्वीकार भी कर लिया था। इनके क्रियान्वयन का अंतिम बार हिसाब मई 2012 में दिया गया था। तब यह संख्या 533 दर्ज की गई थी और उसके बाद कभी इनकी गिनती ही नहीं हुई। यह सही है कि दिसंबर 2023 तक 1,562 अप्रासंगिक हो चुके पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। इसी क्रम में जन विश्वास अधिनियम, 2023 के जरिये 183 प्रविधानों को आपराधिक बंदिश से मुक्त किया गया। वर्ष 2017 के बजट से योजनागत और गैर-योजनागत व्यय का भेद समाप्त कर दिया गया। ये तमाम सुधार ऐसे हैं, जिनसे व्यवस्था के भीतरी तंत्र के विशेषाधिकारों पर जरा भी आंच नहीं आई। जबकि जिन सुधारों को दफन कर दिया गया, वे सत्ता प्रतिष्ठान की मानसिकता को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। मंत्रालयों के एकीकरण या उन्हें सुगठित बनाने का यही अर्थ है कि नेताओं के विशेषाधिकारों पर चोट होना। सिविल सेवाओं के लिए एक कड़ा कानून भी अधिकारियों के सुरक्षा आवरण और सुविधावादी रवैये पर आघात करता है। असल में जब कुछ समूह अपने निहित स्वार्थों के लिए लामबंद होते हैं, तो सुधार वहीं दम तोड़ देते हैं। इस क्रम में विशेषाधिकार संपन्न वर्ग अपने मनमाने अधिकारों या विवेकाधिकारों की रक्षा में उतर आता है। भारत में सुधारों का क्रियान्वयन उनकी उपयोगिता या योग्यता से नहीं, बल्कि इस बात से निर्धारित हुआ है कि उनकी आंच किसको झेलनी पड़ेगी। स्पष्ट है कि यहां बीमारी पहचान करने में कोई समस्या नहीं, बल्कि वास्तविक समस्या उसके उपचार की है कि उसमें किसकी जवाबदेही तय की जाए। स्पष्ट है कि सुधारों की राह में परियोजनाओं की पूर्णता को लेकर अनुशासन बरतना होगा।

असहनीय हो चुकी है न्याय में देरी

इस कथन से शायद ही कोई अपरिचित हो कि "न्याय में देरी न्याय से वंचित करना है, लेकिन बार-बार की देरी तो अन्याय है।" महान संवैधानिक विशेषज्ञ एवं न्यायविद् नानी पालकीवाला का यह कथन भी खूब प्रचलित है कि भारत में न्याय प्रशासन की सबसे बड़ी खामी देरी है और मैं दुनिया के किसी भी ऐसे देश से अवगत नहीं जहां मुकदमे इतने लंबे समय तक चलते हों, जितने भारत में। उनका यह भी कहना था, भारत में कानून बहुत ज्यादा हैं और न्याय बहुत कम। ये सभी चर्चित कथन भारतीय न्यायपालिका के समक्ष खड़ी चुनौतियों की गंभीरता को ही बयान करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल में नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी और नेशनल कंपनी ला अपीलेट ट्रिब्यूनल अर्थात एनसीएलएटी की प्रशासनिक स्वतंत्रता पर गंभीर चिंता जताते हुए यह टिप्पणी करना कि इन संस्थाओं को कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 'पूरी तरह हाईजैक' कर लिया है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि केवल विशेष ट्रिब्यूनल या न्याय मंच बना देने भर से त्वरित न्याय सुनिश्चित नहीं हो जाता। इन संस्थाओं में भारी रिक्तियों, बुनियादी ढांचे के अभाव और प्रशासनिक नियंत्रण में ढिलाई के कारण मुकदमों का निपटारा हफ्तों या महीनों में होने के बजाय सालों-साल खिंच जाता है, जिससे व्यावसायिक विवादों और आम नागरिकों को भारी आर्थिक और मानसिक क्षति होती है। यह विडंबना ही है कि जिन विशेष संस्थाओं का गठन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए किया गया था, वे स्वयं प्रशासनिक और व्यवस्थागत जकड़न का शिकार हैं। निचली अदालतों, अपीलीय ट्रिब्यूनलों और न्याय के अन्य मंचों पर मुकदमों के निस्तारण में लंबी देरी और कई बार आने वाले अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण फैसलों का एक सबसे बड़ा कारण जवाबदेही का पूर्ण अभाव है। अक्सर निचली अदालतों द्वारा पारित सतही या कानूनी रूप से कमजोर निर्णयों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है और उन पर कड़ी टिप्पणियां भी की जाती हैं, परंतु यह बात कभी सार्वजनिक नहीं होती कि ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ अंततः क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई? इसके विपरीत इन न्यायाधीशों की पदोन्नति का आधार और आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली पूरी तरह से अपारदर्शी है, जिससे आम जनता और विशेष रूप से वादियों के मन में न्याय व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। इस दोहरी चुनौती से पार पाने के लिए यह समझना आवश्यक है कि व्यवस्था की कमजोरी केवल प्रशासनिक या बुनियादी ढांचे के अभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक अनुशासन की कमी भी है। एक तरफ जहां कार्यपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह न्यायिक संस्थाओं को पर्याप्त संसाधन और स्टाफ देकर उनकी गति को बाधित करने वाले कारणों का निवारण करे, वहीं दूसरी तरफ न्यायपालिका के भीतर भी न्यायाधीशों की जिम्मेदारी बनती है कि वे उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए बिना अनावश्यक विलंब के त्वरित निर्णय दें। केवल बुनियादी ढांचे की कमी को ही देरी का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि न्यायाधीशों के पास अपनी कार्यशैली और समय-प्रबंधन में सुधार करके स्थिति को काफी हद तक बेहतर बनाने की शक्ति होती है। इसका उन्हें उपयोग करना ही चाहिए। न्याय में देरी की विकट समस्या से निपटने के लिए केवल निचली अदालतों ही नहीं, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय सहित संपूर्ण न्याय तंत्र की जवाबदेही तय करना अनिवार्य हो गया है, ताकि लोगों को समय पर सही न्याय मिल सके। प्रख्यात न्यायविदों और न्यायिक सुधारों पर बल देने वालों का यह स्पष्ट मत रहा है कि जब तक न्यायपालिका अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली में आधुनिक प्रबंधन और कड़े अनुशासन को नहीं अपनाती, तब तक केवल नए-नए कानून बना देने से स्थिति नहीं सुधरेगी।

इस दिशा में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के साथ विधि आयोगों ने बार-बार इस पर बल दिया है कि मुकदमों की सुनवाई के दौरान तारीख पर तारीख की संस्कृति पर कड़ाई से रोक लगनी चाहिए और अनावश्यक रूप से मामले को लटकाने वाले वकीलों या पक्षों पर भारी वित्तीय दंड लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही उच्चतर न्यायपालिका से लेकर अधीनस्थ अदालतों तक हर स्तर पर यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि बहस पूरी होने के बाद एक निश्चित समयसीमा के भीतर पारदर्शी निर्णय दिए जाएं। इस तय सीमा का पालन न होने पर संबंधित पीठासीन अधिकारी की कड़ाई से वार्षिक समीक्षा हो। मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए पूर्व न्यायविदों द्वारा 'केस मैनेजमेंट कांफ्रेंस' की जो वकालत की गई है, उसे जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। इस व्यवस्था के तहत न्यायाधीश दोनों पक्षों के वकीलों के साथ बैठकर शुरुआत में ही विवाद के मुख्य बिंदुओं को तय करते हैं, जिससे सुनवाई के दौरान अनावश्यक और लंबी बहसों से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त चूंकि खुद सरकार देश के कुल मुकदमों के एक बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार है, अतः उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न कानूनी समितियों ने लगातार यह सिफारिश की है कि सरकारी विभागों को हर मामले में विपरीत निर्णय के बाद आंख मूंदकर अपील करने से रोका जाना चाहिए।

इसके लिए आंतरिक जांच समितियां बनाकर अक्षम अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना आवश्यक है, ताकि वे लोगों, सरकारी संसाधनों और साथ ही अदालतों का समय बर्बाद करने से बचें। भारतीय न्याय प्रणाली का कायापलट केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता नहीं, बल्कि देश के सामाजिक-आर्थिक विकास की एक अनिवार्य शर्त है।

जोखिम बढ़ाता बढ़ता व्यापार घाटा

हाल में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे की चुनौती का सामना कर रहा है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2015-16 के 52.5 अरब डालर से दोगुने से अधिक होकर 2025-26 में 112 अरब डालर हो गया। हालांकि चीन को भारत के निर्यात में वृद्धि हुई है, लेकिन वहां से आयात की बड़ी मात्रा व्यापार घाटे को और बढ़ा रही है। चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक असंतुलन के पीछे कई संरचनात्मक और नीतिगत कारक जिम्मेदार हैं। इसका प्रमुख कारण चीन की गैर-शुल्क बाधाएं हैं। वित्त मंत्री के अनुसार, चीनी प्रशासन के जटिल तकनीकी, स्वास्थ्य और गुणवत्ता मानक भारतीय वस्तुओं के चीनी बाजार में प्रवेश को बाधित करते हैं। भारत एक दशक से अधिक समय से अपनी जेनेरिक दवाओं, प्रसंस्कृत मांस और कृषि उत्पादों के लिए चीनी बाजार में उचित पहुंच की मांग करता रहा है। जबकि चीन घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए जटिल नियम लागू करता है। इसके चलते भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धी कीमतों और गुणवत्ता के बावजूद चीनी बाजार में अपनी जगह नहीं बना पाते। इसके अलावा चीनी युआन की विनिमय दर के उतार-चढ़ाव से भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ता है। चीन के साथ व्यापारिक असंतुलन का एक अन्य पहलू 'मेक इन इंडिया' अभियान के बावजूद चीनी कच्चे माल और घटकों पर भारत की निर्भरता है। हालांकि भारत का घरेलू विनिर्माण क्षेत्र हाल के वर्षों में बढ़ा है, लेकिन औद्योगिक उत्पादन अब भी चीनी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। भारत का इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, डिस्प्ले पैनल, सोलर पीवी सेल, औषधीय कच्चा माल यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इन्ग्रीडिएंट्स (एपीआइ) और भारी औद्योगिक मशीनरी के लिए चीन से आयात पर निर्भरता बनी हुई है। इस निर्भरता के कारण भारत में औद्योगिक उत्पादन और विनिर्माण बढ़ने के साथ चीनी कलपुर्जों का आयात भी बढ़ता है। साथ ही चीन ने दुर्लभ मृदा तत्वों, लीथियम और आधुनिक उर्वरकों के उत्पादन एवं निर्यात पर नियंत्रण स्थापित कर रखा है। ये संसाधन भारत के इलेक्ट्रानिक्स उद्योग, इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर ऊर्जा और कृषि क्षेत्र के लिए आवश्यक हैं। इनकी सीमित आपूर्ति और ऊंची कीमतों के कारण भारत को हर साल बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे को नियंत्रित करने के लिए केवल जवाबी सीमा शुल्क लगाना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। इसके बजाय भारत को व्यापक रणनीति अपनानी होगी। इसकी पहली प्राथमिकता इलेक्ट्रानिक्स और सेमीकंडक्टर का घरेलू इकोसिस्टम विकसित करना होना चाहिए। भारत को अंतिम उत्पादों की असेंबलिंग के बजाय घटक स्तर पर निर्माण बढ़ाना होगा। जब तक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, एडवांस्ड सेंसर, डिस्प्ले पैनल और सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन देश में शुरू नहीं होता, तब तक चीन पर निर्भरता समाप्त नहीं होगी। दूसरा कदम फार्मास्यूटिकल्स और बल्क ड्रग क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है, लेकिन उसका दवा उद्योग एपीआइ के लिए 70 प्रतिशत तक चीन पर निर्भर है। यह निर्भरता रणनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी जोखिम पैदा करती है। इस निर्भरता को कम करने के लिए देश में घोषित बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना तेज करनी होगी और 41 महत्वपूर्ण एपीआइ के घरेलू उत्पादन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू करनी होंगी। साथ ही चीन की गैर-शुल्क बाधाओं का मुकाबला करने के लिए भारत को कूटनीतिक प्रयासों के साथ देश में क्वालिटी कंट्रोल आर्डर लागू करने होंगे। अमानक चीनी सामान की डंपिंग रोकने के लिए गुणवत्ता मानक तय करना जरूरी है, ताकि घरेलू विनिर्माताओं को प्रतिस्पर्धा का उचित माहौल मिल सके। भारत को आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने और 'फ्रेंड-शोरिंग' की नीति अपनानी होगी। क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ धातुओं और उच्च तकनीकी उत्पादों के लिए चीन पर निर्भरता घटाने के उद्देश्य से समान विचारधारा वाले देशों के साथ वैकल्पिक आपूर्ति नेटवर्क तैयार करना होगा। ग्रीन टेक्नोलाजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार के दौर में यदि भारत ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा नहीं दिया तो जीवाश्म ईंधन के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भरता कम होने के बाद चीन से हरित प्रौद्योगिकी के आयात पर निर्भरता बढ़ सकती है। चीन से बढ़ता व्यापार घाटा केवल आयात-निर्यात का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक स्थिरता, औद्योगिक क्षमता और रणनीतिक संप्रभुता से जुड़ा विषय है। इसीलिए हमें घरेलू वस्तुओं की खरीद को प्राथमिकता बनाना होगा। हमें चीन को आर्थिक प्रतिस्पर्धी मानते हुए उससे मुकाबले के प्रयास करने होंगे। उद्योग और कारोबार में शोध एवं नवाचार के लिए संसाधन बढ़ाने होंगे। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआइ) योजनाओं के पारदर्शी और समयबद्ध क्रियान्वयन, गुणवत्ता मानकों के पालन तथा व्यापारिक साझेदारों के विविधीकरण के प्रयासों को गति देनी होगी। इन प्रयासों से भारत चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता और व्यापार घाटे को चरणबद्ध ढंग से कम कर वैश्विक व्यापार में एक संतुलित और आत्मनिर्भर आर्थिक शक्ति के रूप में उभरेगा।

कभी बर्थडे पर केक खरीदने तक के नहीं थे पैसे, आज इतने करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं शाहरुख खान



बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे। कभी केक खरीदने तक के पैसे नहीं थे, आज 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। शाहरुख खान 2 नवंबर 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाएंगे। हुरून इंडिया रिच लिस्ट के मुताबिक उनकी अनुमानित नेटवर्थ 12 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा है। KKR, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और ब्रांड एंडोर्समेंट उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत हैं। बचपन में उनके पास जन्मदिन पर केक खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 2 नवंबर 2026 को अपना 61वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब उनके परिवार के पास जन्मदिन पर केक खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज किंग खान करोड़ों रुपये के मालिक हैं। फिल्मों से लेकर क्रिकेट टीम और बिजनेस तक शाहरुख ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 50 रुपये से शुरू किया था अपना करियर आज शाहरुख खान को दुनिया भर में पहचान हासिल है, लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर आसान नहीं रहा। एक्टर ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। दूरदर्शन के शो से पहचान बनाने वाले शाहरुख ने शुरुआती दिनों में सिर्फ 50 रुपये कमाए थे। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और अपनी मेहनत और शानदार एक्टिंग के दम पर इंडस्ट्री में बादशाहत कायम कर ली। कभी बर्थडे पर केक खरीदने के नहीं थे पैसे शाहरुख खान ने एक पुराने इंटरव्यू में अपने बचपन से जुड़ा दिलचस्प किस्सा शेयर किया था। उन्होंने बताया था कि उनका परिवार लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था और बचपन में उनके पास जन्मदिन पर केक खरीदने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। यही वजह थी कि उनके जन्मदिन पर कभी बड़े जश्न नहीं मनाए जाते थे। आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और हर साल उनके बर्थडे पर देश-विदेश में फैंस जश्न मनाते हैं। 12,490 करोड़ रुपये है किंग खान की नेटवर्थ शाहरुख खान की संपत्ति की बात करें तो हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार उनकी अनुमानित नेटवर्थ करीब 12,490 करोड़ रुपये बताई गई है। वह भारत के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल हैं। उनकी कमाई सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई बड़े बिजनेस और निवेश भी उनकी संपत्ति का हिस्सा हैं। KKR से लेकर रेड चिलीज तक फैला है व्यापार शाहरुख खान की कमाई के प्रमुख स्रोतों में उनकी आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स, प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और बड़े ब्रांड्स के एड्स शामिल हैं। इसके अलावा फिल्मों में एक्टिंग और प्रोडक्शन से भी वह मोटी कमाई करते हैं। यही वजह है कि उनका नाम सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी काफी बड़ा है। मन्नत से दुबई तक करोड़ों की संपत्ति शाहरुख खान की लग्जरी लाइफस्टाइल भी हमेशा चर्चा में रहती है। मुंबई स्थित उनका आलीशान बंगला मन्नत किसी पहचान का मोहताज नहीं है।

ऋतिक रोशन ने सबा आजाद को बताया अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा, जन्मदिन पर किया प्यार का इजहार



ऋतिक रोशन ने सबा आजाद के 40वें जन्मदिन पर रोमांटिक पोस्ट शेयर किया। फ्लाइट के उदाहरण से उन्होंने बताया कि सबा के साथ मुश्किल रास्ता भी उनके लिए खास और रोमांचक सफर बन जाता है। ऋतिक रोशन ने 1 नवंबर को गर्लफ्रेंड सबा आजाद के 40वें जन्मदिन पर खास पोस्ट शेयर किया। अभिनेता ने फ्लाइट के दो विकल्पों का उदाहरण देकर सबा के साथ अपने रिश्ते को बयां किया। ऋतिक ने कहा कि वह सबा के साथ हमेशा मुश्किल और लंबे रास्ते को चुनना पसंद करेंगे। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन और सबा आजाद अपने रिश्ते को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। दोनों पिछले कुछ वर्षों से एक-दूसरे के साथ हैं और सोशल मीडिया पर भी खुलकर प्यार जाहिर करते हैं। अब 1 नवंबर को सबा के 40वें जन्मदिन पर ऋतिक ने उनके लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है। अभिनेता ने इस पोस्ट में एक दिलचस्प उदाहरण के जरिए बताया कि सबा के साथ जिंदगी का हर सफर उनके लिए कितना खास है।

यश के बेटे को पसंद नहीं आया पापा का रावण अवतार, बेटे ने कह दिया बुरा इंसान



सुपरस्टार यश ने खुलासा किया है कि फिल्म रामायण में उनके द्वारा रावण का रोल निभाने पर उनके छोटे बेटे यथर्व ने नाराजगी जताते हुए उन्हें बुरा आदमी कहा है। एक्टर यश फिल्म रामायण में रावण का किरदार निभा रहे हैं। बेटे यथर्व को पिता का रावण बनना पसंद नहीं आया। यथर्व ने पाप यश को बुरा इंसान तक कह दिया। फिल्म में रणबीर कपूर राम और साई पल्लवी सीता का किरदार निभा रहे है। फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई बड़ा एक्टर किसी नेगेटिव रोल को चुनता है, तो उसका असर केवल बड़े पर्दे पर ही नहीं बल्कि उसके निजी जीवन और परिवार पर भी पड़ता है। इन दिनों अपनी फिल्मों को लेकर चर्चा में रहने वाले साउथ के सुपरस्टार यश के साथ कुछ ऐसा ही दिलचस्प किस्सा सामने आया है। उनकी आने वाली भव्य फिल्म रामायण को लेकर सिने प्रेमियों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़ा एक ऐसा व्यक्तिगत किस्सा सामने आया है जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बेटे ने पूछा ऐसा सवाल जिसे सुन हैरान रह गए यश यश ने हाल ही में शेयर किया कि जब उनके बेटे यथर्व को यह पता चला कि उनके पिता आने वाली पौराणिक फिल्म में रावण का रोल निभा रहे हैं, तो उसका रिएक्शन काफी हैरान करने वाला था। मासूमियत भरे अंदाज में बेटे ने सीधे तौर पर अभिनेता से सवाल कर डाला कि क्या वह सचमुच रावण हैं। इस तरह के अप्रत्याशित सवाल की उम्मीद शायद यश ने खुद भी नहीं की होगी, क्योंकि बच्चे आमतौर पर अपने पिता को हमेशा परदे पर एक हीरो के रूप में ही देखने के आदी होते हैं। मासूमियत भरे गुस्से में बेटे ने कह डाली बड़ी बात जब एक्टर यश ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि यह केवल सिनेमा है और वह फिल्म के लिए यह रोल निभा रहे हैं, तो बच्चे का जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। बेटे ने तपाक से जवाब देते हुए कहा कि आप एक बुरे इंसान हैं और आप ऐसा रोल कैसे निभा सकते हैं। एक पिता के लिए अपने बच्चे को यह समझाना बेहद मुश्किल हो गया कि एक्टिंग और रीयल लाइफ में बहुत अंतर होता है, और कलाकारों को कहानी की डिमांड के अनुसार अलग-अलग रंग दिखाने पड़ते हैं। राम और रावण के अंतर को बेटे को समझाना मुश्किल परिवार के अंदर बच्चों को सही और गलत का पाठ पढ़ाना किसी भी माता-पिता के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक्टर यश को न केवल अपने एक्टिंग को लेकर सफाई देनी पड़ी, बल्कि उन्हें अपने बेटे को रामायण की मूल कहानी और भगवान राम के आदर्शों के बारे में भी पूरी तरीके से बताना पड़ा। यश ने अपने बच्चे को समझाया कि जीवन में हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए और रावण भले ही कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। इस पूरी बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि बच्चा पर्दे के रोल को असल जिंदगी के आदर्श के रूप में न अपना ले।

विजय हजारे ट्रॉफी से रोहित शर्मा की घरेलू क्रिकेट में वापसी, मुंबई MCA को दिया अपडेट



रोहित शर्मा दिसंबर में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम के लिए खेलते नजर आएंगे। 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले गेम फिटनेस बनाए रखने के लिए रोहित का यह फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। रोहित शर्मा दिसंबर में होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई टीम के लिए खेलेगें इस संबंध में रोहित ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) को सूचित कर दिया रोहित ने 2027 वर्ल्ड कप से पहले अपनी गेम फिटनेस और लय बरकरार रखने के लिए लिया ये फैसला भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक बार फिर मुंबई की जर्सी में घरेलू क्रिकेट के मैदान पर धमाल मचाने के लिए तैयार हैं।

टीम इंडिया की हार के बावजूद श्रेयस अय्यर-ईशान किशन ने रचा इतिहास, बनाए महारिकॉर्ड



भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवां टी-20 मैट 7 विकेट से हार गई है। हालांकि टीम इंडिया ने सीरीज 3-2 से अपने नाम की। श्रेयस अय्यर-ईशान किशन ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया। न्यूजीलैंड ने आखिरी टी-20 मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हराया भारत ने 5 मैचों की यह टी-20 सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने इस मुकाबले में एक महॉरिकॉर्ड भी बना दिया न्यूजीलैंड ने सीरीज के पांचवें और आखिरी टी-20 मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भले ही इस मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा हो, लेकिन शुरुआती मैचों में शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 5 मैचों की यह टी-20 सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली है। हैमिल्टन में खेले गए इस मैच में कीवी टीम ने भारत से मिले 192 रन के लक्ष्य को मात्र 18 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट और ग्लेन फिलिप्स की आतिशी बल्लेबाजी 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और फिन एलन (2) के रूप में उन्हें पहला झटका जल्दी लग गया। इसके बाद टिम साइफर्ट और डेरिल मिचेल (29) ने पारी को संभाला। साइफर्ट ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 50 गेंदों पर 93 रनों की पारी खेली। साइफर्ट के आउट होने के बाद ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला और 65 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम को 12 गेंद शेष रहते ही जीत दिला दी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और नीतीश रेड्डी को 1-1 विकेट मिला। ईशान और अय्यर के अर्धशतक इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन (4) और अभिषेक शर्मा (1) सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला।

डोनाल्ड ट्रंप का वॉल स्ट्रीट जर्नल पर दायर मुकदमा खारिज, जज बोले- ट्रंप की दलीलें बेबुनियाद

द वॉल स्ट्रीट जर्नल मामले में मियामी के जज डैरिन गेल्स ने कहा कि ट्रंप ये साबित नहीं कर पाए कि अखबार ने जानबूझकर दुर्भावना से ये खबर छापी थी। वॉ अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रम्प का 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' अखबार और उसके मालिक रूपर्ट मर्डोक पर किया गया अरबों डॉलर का मुकदमा खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये साबित करने में विफल रहे कि अखबार ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से उनके खिलाफ रिपोर्ट छापी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए थे आरोप बता दें कि 'द वॉल स्ट्रीट जर्नल' का नाम जेफरी एप्सटीन (Jeffrey Epstein) से जुड़ी फाइलों और रिपोर्टिंग के कारण काफी चर्चा में रहा है। इस अखबार ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें दावा किया गया था कि वर्ष 2003 में जेफरी एप्सटीन के 50वें जन्मदिन के लिए तैयार किए गए एक एल्बम में उत्तेजक पत्र शामिल था, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का हस्ताक्षर होने की बात भी की थी। इस पत्र में एक बिना कपड़ों वाली महिला का स्केच बना था और अंत में एप्सटीन को जन्मदिन की बधाई दी गई थी। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत



में इसे झूठा बताते हुए कहा था कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपनी मानहानि बताते हुए अखबार और उसके मालिक रूपर्ट मर्डोक पर केस फाइल कर दिया था जिसे अब खारिज कर दिया गया है। Wall Street Journal मामले में जज ने क्या कहा ? द वॉल स्ट्रीट जर्नल मामले में मियामी के जज डैरिन गेल्स ने कहा कि ट्रंप ये साबित नहीं कर पाए कि अखबार ने जानबूझकर दुर्भावना से ये खबर छापी थी। उनकी दलीलें बेबुनियाद थीं। जज ने ये भी कहा कि ट्रंप जबरन अखबार की जांच-पड़ताल में कमियां निकालने की कोशिश कर रहे थे। ल स्ट्रीट जर्नल पर दायर मुकदमा खारिज ट्रंप ने अखबार और उसके मालिक पर लगाया था आरोप ट्रंप ने अखबार पर लगाया था मानहानि का आरोप अब दोबारा अदालत में नहीं जा पाएगा ये मामला बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल मामले में अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो स्थायी तौर पर सुनाया है। ट्रंप अब इस मामले को दोबारा अदालत में नहीं ले जा सकते हैं। आखिर कौन था जेफरी एप्सटीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम आए दिन जेफरी एप्सटीन के साथ जोड़ा जाता रहा है। एप्सटीन फाइल्स में कई जगहों पर दोनों की तस्वीरें भी एक साथ दिखी हैं। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कौन है जेफरी एप्सटीन जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ था। यौन अपराधी एप्सटीन संयुक्त राज्य अमेरिका का एक करोड़पति फाइनेंसर था। उसकी बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी। 2019 में जेफ्री एप्सटीन को सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। लेकिन मुकदमे से पहले ही उसने जेल में आत्महत्या कर ली।

पाकिस्तान की जीत पर क्या बोल गए शहबाज शरीफ? पाकिस्तानियों ने ही लगा दी क्लास



पाकिस्तान की श्रीलंका पर जीत के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। भारत के खिलाफ जीत पर उनके पुराने पोस्ट को लेकर यूजर्स ने सवाल उठाए। पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर वनडे ट्राई-सीरीज का खिताब जीता शहबाज शरीफ भारत के खिलाफ पुराने पोस्ट को लेकर ट्रोल हुए फखर जमान ने फाइनल में 127 रन की शानदार पारी खेली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बार फिर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। मामला पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए उनके पोस्ट से जुड़ा है। पाकिस्तान ने शनिवार को वनडे ट्राई-सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। शहबाज शरीफ ने टीम की इस जीत के बाद खिलाड़ियों को बधाई दी, लेकिन उनकी पोस्ट की तुलना भारत के खिलाफ पाकिस्तान की पिछली जीत पर किए गए संदेश से होने लगी। इसके बाद से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सोशल मीडिया पर जमकर बेइज्जत किया जा रहा है। जीत के बाद शरीफ ने दी टीम को बधाई पाकिस्तान की जीत के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर टीम की तारीफ की। उन्होंने फखर जमान की शतकीय पारी और अराफात मिन्हास तथा हसन नवाज के बीच हुई साझेदारी का विशेष रूप से उल्लेख किया। शरीफ ने अपनी पोस्ट में लिखा, बधाई हो, पाकिस्तान! लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ट्राई-सीरीज के फाइनल में श्रीलंका पर ऐतिहासिक जीत। फखर जमान की शानदार सेंचुरी, उसके बाद दो उभरती प्रतिभाओं अराफात मिन्हास और हसन नवाज के बीच बेहतरीन साझेदारी। यह शानदार प्रबंधन, टीमवर्क और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन है। उन्होंने खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी और टीम का समर्थन करने वाले लाखों प्रशंसकों को भी बधाई दी।

रूस की तेल रिफाइनरी पर यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला, आसमान में उठे धुएं के गुबार



यूक्रेन ने रूस के समारा क्षेत्र में नोवोकुयबिशेवस्क तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद भीषण आग लग गई। यूक्रेन ने रूस की नोवोकुयबिशेवस्क तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी में लगी भीषण आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार। ट्रंप प्रशासन के दबाव के बाद दो सप्ताह से रुके थे रूसी तेल ठिकानों पर हमले। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। यूक्रेन ने शुक्रवार को रूस के समारा क्षेत्र में स्थित एक बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया। हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई और आसमान में धुएं के ऊंचे गुबार दिखाई देने लगे। खास बात यह है कि रूस की तेल प्रसंस्करण इकाइयों पर यूक्रेन का हमला करीब दो सप्ताह के अंतराल के बाद हुआ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वैश्विक स्तर पर ईंधन की बढ़ती कीमतों का हवाला देते हुए यूक्रेन पर रूस की तेल सुविधाओं पर हमले रोकने का दबाव बनाया था। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले मिडटर्म चुनावों से पहले यह दबाव बढ़ा था।

इसके बाद यूक्रेन ने रूसी तेल प्रतिष्ठानों पर हमले अस्थायी रूप से रोक दिए थे। यह विराम अमेरिकी चुनाव के बाद तक जारी रहने की उम्मीद थी। ड्रोन हमले के बाद रिफाइनरी में लगी आग यूक्रेन के ड्रोन ने नोवोकुयबिशेवस्क तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। हमले के बाद वहां आग लग गई। सोशल मीडिया पर सामने आए 16 सेकंड के एक डैशकैम वीडियो में सड़क से गुजरते वाहन के अंदर से रिफाइनरी के पास उठता धुआं दिखाई दे रहा है।

यह रिफाइनरी रूस की सरकारी नियंत्रण वाली तेल कंपनी रोसनेफ्ट के स्वामित्व में है। इस साल अगस्त के बाद यह दूसरी बार है, जब इसे यूक्रेनी ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है।

गुलामी के लिए भारत से माफी मांगेगा ब्रिटेन! PM एंडी बर्नहैम ने दिया बड़ा बयान, मुआवजे को लेकर कही ये बात



ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार के लिए माफी मांगने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ऐतिहासिक गुलामी के लिए मुआवजा देने से इनकार किया है। एंडी बर्नहैम दास व्यापार के ऐतिहासिक अन्याय पर माफी मांगने को तैयार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गुलामी के लिए मुआवजा देने का विरोध किया किंग चार्ल्स ने भी कैरेबियाई दौरे पर गुलामी के इतिहास का जिक्र किया ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम कॉमनवेल्थ समिट में शामिल होने से पहले ने ट्रांस-अटलांटिक दास व्यापार को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वह इस ऐतिहासिक अन्याय के लिए खुले मन से माफी मांगने को तैयार हैं।

ईरान पर भड़के मार्को रुबियो, बोले- 100 साल पीछे ले जा रहा देश, परमाणु हथियार मिले तो पूरी दुनिया के लिए खतरा



अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान पर मध्य-पूर्व में अस्थिरता फैलाने, जहाजों पर हमले करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को परमाणु हथियार मिलना खतरनाक होगा। मार्को रुबियो ने ईरान को दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले करने का लगाया आरोप। रुबियो ने कहा, ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा ट्रंप प्रशासन। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने तेहरान की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने ईरान पर मध्य पूर्व में अस्थिरता फैलाने, व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाने और अपने ही नागरिकों की हत्या करने का आरोप लगाया। रुबियो ने चेतावनी दी कि अगर ऐसे शासन के हाथ परमाणु हथियार लग गए तो पूरी दुनिया के सामने गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान की गतिविधियां दुनिया को 80 से 100 साल पीछे के दौर में ले जा रही हैं। भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर हमले का आरोप शनिवार को एक बयान में रुबियो ने कहा कि ईरान जहाजों को उड़ा रहा है। इनमें ऐसे व्यापारिक जहाज भी शामिल हैं, जिन पर भारतीय नाविक सवार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान उन जहाजों को भी निशाना बना रहा है, जो उन देशों के लिए ऊर्जा और ईंधन लेकर जा रहे हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे से जुड़े हैं। रुबियो ने कहा कि दुनिया के सामने ऐसी स्थिति है, जहां एक देश खुलेआम व्यापारिक जहाजों को उड़ाने की बात कर रहा है। उन्होंने इसे बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि इसका असर दुनिया के हर देश पर पड़ रहा है। ईरान से बातचीत का रास्ता अभी खुला अमेरिकी विदेश मंत्री ने ईरान के साथ बातचीत को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए कोई निश्चित समयसीमा तय नहीं है और इस पर फैसला लेना राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अधिकार है। रुबियो के मुताबिक, ईरान के साथ बातचीत कभी पूरी तरह बंद नहीं हुई। दोनों पक्षों के बीच सीधे और मध्यस्थों के जरिए लगातार संपर्क होता रहा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकता विवादों को कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना है।

'सेवा संकल्प अभियान' सफल, हजारों

और प्रशासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। केवल आवेदन स्वीकार करना इस अभियान का उद्देश्य नहीं है, बल्कि वास्तविक रूप से कितने नागरिकों की समस्याओं का समाधान हुआ और कितने परिवारों को राहत मिली, यही अभियान की सफलता का असली पैमाना है। उन्होंने महिला किसानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम बनाने तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने देने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभाने का निर्देश भी दिया। 'सेवा संकल्प अभियान' के सफल आयोजन से मीरा-भाईंदर के नागरिकों में संतोष और उत्साह का माहौल है। इस पहल से सरकारी व्यवस्था के प्रति आम जनता का विश्वास मजबूत होने की उम्मीद जताई गई है।

हम रिजीम चेंज की ओर बढ़ रहे

फायरब्रांड सांसद संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते केंद्र सरकार के खिलाफ बेहद कड़े और तीखे शब्दों में अपनी बात रखी। संजय राउत ने पूरे आत्मविश्वास के साथ हुंकार भरते हुए कहा, क्रांति आ रही है... क्रांति! हम रिजीम चेंज की तरफ जा रहे हैं। उनके इस बयान ने दिल्ली के सियासी गलियारों से लेकर पूरे देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। जनसैलाब और बैरीकेडिंग पर सरकार को चेतावनी राउत ने मीडिया से बातचीत के दौरान रैली में पहुंच रहे जनसैलाब और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से लाखों की संख्या में आम नागरिक और कार्यकर्ता दिल्ली की CMO में प्रवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों को इस रैली में भाग लेने से रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर काफी कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि, संजय राउत ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि सरकार और प्रशासन उन्हें रोकने की जितनी अधिक कोशिश करेगा, लोगों का आक्रोश और रैली में आने वाली भीड़ का आकार उतना ही बड़ा और विशाल होता चला जाएगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि देश की जनता अब सत्ता परिवर्तन का मन बना चुकी है और वह इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करेगी। जनता तमाम सरकारी बैरीकेडिंग और रुकावटों को तोड़ते हुए हर हाल में रामलीला मैदान तक पहुंचेगी। किसी एक पार्टी की नहीं, पूरे देश की ताकत रामलीला मैदान से देश को दिए जा रहे संदेश की व्याख्या करते हुए शिवसेना (UBT) सांसद ने कहा कि यह आयोजन महज किसी एक राजनीतिक पार्टी या गठबंधन की ताकत दिखाने का मंच नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज रामलीला मैदान के मंच से जो शक्ति दिखाई जा रही है, वह वास्तव में किसी एक दल की शक्ति न होकर पूरे भारत देश की जनता की सामूहिक ताकत है। जनता अब मौजूदा सरकार को और आगे सहन नहीं करना चाहती है और वह देश में व्यापक बदलाव चाहती है। राउत ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के इस प्रकार के बड़े और राष्ट्रीय स्तर के विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम आने वाले समय में भी लगातार आयोजित होते रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे सभी राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम दिल्ली के केंद्र में, सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की आंखों के ठीक सामने आयोजित किए जाएंगे। व्यापारी वर्ग और शीर्ष नेतृत्व पर तंज रैली और विरोध प्रदर्शनों से देश के व्यापारियों व अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव के सवाल पर भी संजय राउत ने बेहद बेबाक और तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश के आम व्यापारियों और छोटे कारोबारियों को इस आंदोलन या रैली से किसी भी प्रकार की कोई वास्तविक चिंता या परेशानी नहीं है। देश के आर्थिक व राजनीतिक हालात पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि इस समय भारत में केवल दो ही बड़े व्यापारी मौजूद हैं मोदी और अमित शाह। उन्होंने कहा कि असल में आर्थिक या राजनीतिक नुकसान सिर्फ इन दोनों 'व्यापारियों' का हो रहा है। संजय राउत ने दोटूक अंदाज में कहा कि अगर जनता के इस प्रकार के विशाल आंदोलनों से इन दो 'व्यापारियों' को कोई नुकसान झेलना पड़ता है, तो हो जाने दीजिए, क्योंकि देश की जनता अब अपने लोकतांत्रिक अधिकारों और बदलाव के लिए मैदान में उतर चुकी है।

INDI गठबंधन का शक्ति

लाने का पहला कदम ज्ञानेश कुमार को हटाना है। विपक्षी INDI गठबंधन की रामलीला मैदान में रविवार को वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में जुटी भारी भीड़ का वोट चोरी के खिलाफ मजबूत संदेश देने के लिए आभार जताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार को जो संदेश देना था वह लोगों ने दे दिया है। यह आवाज किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि देश के युवाओं, किसानों और मजूदरों की साफ आवाज है कि हम लोकतंत्र को नष्ट नहीं होने देंगे चाहे आप खुद को जितना भी बड़ा समझें, संविधान से बड़े नहीं हो सकते। विपक्षी गठबंधन के मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, फारूख अब्दुल्ला जैसे तमाम शीर्षस्थ नेताओं की मंच पर मौजूदगी के बीच राहुल गांधी ने बंगाल का चुनाव लूटने की ममता की बात का समर्थन करते हुए दावा किया कि सालों से वोट चोरी हो रही है। मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, कर्नाटक और 2024 के लोकसभा चुनाव सब में वोट चोरी हुई है। 2024 चुनाव के बाद 13.3 करोड़ वोटर मतदाता सूची से हटाए गए यानि 15 प्रतिशत वोटर बाहर किए गए। जबकि 2024 में एनडीए और विपक्ष के बीच केवल तीन प्रतिशत वोटों का फर्क था इसका मतलब है कि यह चोरी का चुनाव था और यह बात खुद चुनाव आयोग कह रहा है। रैली के लिए खरगे के आवास से एक साथ निकले विपक्षी दिग्गजों के साथ राहुल गांधी ने कुछ किलोमीटर तक खुली जीप में सवार होकर सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ के साथ मार्च करते हुए रामलीला मैदान पहुंचे। सबसे आखिरी में बोलते हुए राहुल गांधी ने सीईसी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार का कृत्य कोई सामान्य चोरी नहीं कानून की भाषा में इसे 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' कहते हैं और यह देशद्रोह है। ज्ञानेश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि वह अब डर से रात को सो नहीं पा रहे क्योंकि देश का गला घोंटा है और सच्चाई यह भी कि न मोदी सो रहे न अमित शाह। वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई को आगे ले जाने के विपक्ष के एजेंडे को साफ करते हुए कांग्रेस नेता ने गृहमंत्री के बयान कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे का सहारा लेते हुए पलटवार किया। राहुल गांधी ने कहा 'अमित शाह कहते हैं कि कि नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे। तो उल्टा मैं बता दूं कि अगर वे जाना भी चाहें तो हम जाने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह आप बात समझिए ज्ञानेश कुमार के बाद हम आपके सामने खड़े होने जा रहे हैं। भूलिए मत जो वोट चोरी की है उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी ही होगी।' भाजपा-संघ पर सीबीआई, ईडी, नौकरशाही, पुलिस से लेकर न्यायपालिका सब पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि हम उनके जैसे नफरत फैलाने वाले नहीं बल्कि देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले हैं और मोदी, शाह, ज्ञानेश या आरएसएस किसी को दुश्मन नहीं मानते। मगर लोकतंत्र और संविधान पर आक्रमण हम स्वीकार करने को तैयार नहीं क्योंकि देश के नागरिकों की आवाज मेरे लिए धर्म से भी जरूरी चीज है। इस आवाज की रक्षा ही मेरा धर्म है। महात्मा गांधी की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति रक्षा की बात के अनुरूप सबसे अंतिम लाइन में खड़े नागरिक की आवाज की रक्षा करने की प्रतिबद्धता जताई। राहुल गांधी ने मोदी-शाह तथा आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे देश कराह रहा है और भाईचारा और मोहब्बत चाह रहा है और हम यही करके दिखांएगे। कांग्रेस नेता ने अदाणी समूह को देश की सारी संपत्तियां सौंपने का आरोप लगाते हुए कहा कि हमें ऐसा देश कतई नहीं बनने देंगे जहां सब कुछ केवल दो-तीन लोगों के पास हो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वोट चोरी की लड़ाई को मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान में तब्दील करने की घोषणा करते हुए कहा कि कि जब तक भाजपा को सत्ता से हटाया नहीं जाता तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी। राजद नेता तेजस्वी यादव ने रामलीला मैदान में विपक्ष के जुटान को 'वोट चोरों' के खिलाफ 'महाभारत' बताते हुए ज्ञानेश कुमार पर प्रहार किया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के एसआईआर का शिकार बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम हारे नहीं, वोट काटकर चुनाव लूटा गया है और हम ऐसा करने वालों को छोड़ेंगे नहीं जान की बाजी लगाकर लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे।

सिर्फ मेट्रो से काम नहीं चलेगा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को चाहिए सुरक्षित और सस्ता परिवहन

महिलाओं को रोजगार स्थल तक पहुंचने में सुरक्षित और सस्ते परिवहन की कमी बड़ी बाधा है, जिससे उनकी कार्यबल भागीदारी प्रभावित होती है। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट ने इस समस्या को उजागर करते हुए महिलाओं के लिए सुगम और किफायती परिवहन साधन बढ़ाने की सिफारिश की है। मेट्रो से लेकर विभिन्न प्रकार के परिवहन साधन विकसित होने के बावजूद भारतीय महिलाओं के एक बड़े वर्ग को अपने घर से लेकर रोजगार के गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाई होती है। तभी विभिन्न प्रकार के रोजगार से जुड़ीं महिलाएं शाम चार बजे तक अपने घर के लिए निकल जाती हैं। रोजगार से जुड़ीं काफी कम महिलाएं शाम छह बजे के बाद काम करती हैं। वित्त मंत्रालय की ताजा मासिक रिपोर्ट में महिलाओं की मोबिलिटी के साधन बढ़ाने की सिफारिश करते हुए इन बातों को उजागर किया गया है। महिलाएं अब भी सुरक्षित और सस्ते परिवहन साधानों की तलाश में हैं।



मेट्रो का जाल देशभर में फैलता जा रहा है, लेकिन मेट्रो से महिलाएं एक निश्चित जगह तक पहुंच पाती है। वहां से उन्हें अपने कार्य के स्थान तक जाने का साधन आसानी से नहीं मिलता। रिपोर्ट में कहा गया है कि सस्ते एवं सुरक्षित परिवहन के साधन आसानी से उपलब्ध होने से महिलाओं में रोजगार बढ़ेंगे। वर्ष 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी महिलाओं से जुड़ी परिवहन की पूरी श्रृंखला को सुगम एवं सस्ता बनाने की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक सुरक्षित परिवहन के साधन के अभाव में महिलाएं महंगे साधन को अपनाती हैं जो अपेक्षाकृत गंतव्य तक पहुंचने में अधिक समय लेते हैं। रिपोर्ट में आईआईटी, मुंबई के सर्वे के हवाले से कहा गया कि जिन जगहों पर महिलाओं की मोबिलिटी को लेकर कड़े नियम थे, वहां मुफ्त बस सेवा स्कीम से विभिन्न प्रकार के रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि महिलाएं विभिन्न कारणों से पुरुषों की तुलना में रोजगार के लिए कम दूरी तक जाना चाहती हैं। यही वजह है कि महिलाओं को प्रतिमाह आने-जाने में औसतन 533 रुपये का खर्च आता है, जबकि पुरुषों को प्रतिमाह 674 रुपये देने पड़ते हैं। महिलाएं घर के पास के रोजगार को अधिक प्राथमिकता देती है। सिर्फ 42 प्रतिशत महिलाएं काम के लिए एक किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करती है। जबकि 62 प्रतिशत पुरुष काम के लिए एक किलोमीटर या उससे अधिक की दूरी तय करते हैं। ग्रामीण इलाके में 65 प्रतिशत महिलाएं अपने काम पर पैदल जाती है। शहरी इलाके में 37.5 प्रतिशत महिलाएं काम पर जाने के लिए आटो या बस सेवा लेती है।

केरलम में सबसे अधिक रोजगार के लिए जाने वाली 47 प्रतिशत महिलाएं बस का इस्तेमाल करती है। तमिलनाडु में 41 प्रतिशत, कर्नाटक में 35 प्रतिशत, तेलंगाना में 29 प्रतिशत महिलाएं बस सेवा से काम पर आती-जाती हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि काम पर जाने की अवधि कम होने पर महिलाएं अधिक समय तक काम कर सकेंगी।

पृष्ठ 1/8 का शेष

मुंबई के 3 सरकारी कॉलेजों

गलतियों और अंकपत्र मिलने में देरी की शिकायत भी की है। हायर और टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि स्टूडेंट्स की शिकायतों के बाद, हायर और टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रकांत दादा पाटिल ने एक रिव्यू मीटिंग की और जरूरी निर्देश जारी किए, सरकार ने बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए छात्रों के लिए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

डिग्री है, लेकिन अदद नौकरी

डॉ. अमोल अंबेकर, महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. करणसिंह गाडे और अन्य पदाधिकारियों ने सरकार से इन मांगों पर विचार करने की अपील की है। संगठन का कहना है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति के योग्य डॉक्टरों को सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में अधिक अवसर मिलने चाहिए। इससे खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है। NHM और सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में अवसर देने की मांग संगठन की पहली मांग है कि बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस डिग्रीधारकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत काम करने का अवसर दिया जाए। इसके अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी उनकी नियुक्ति का रास्ता खोला जाए। समुदाय स्वास्थ्य अधिकारी (CHO) जैसे पदों के लिए भी उन्हें आवेदन करने की अनुमति देने की मांग की गई है। दूसरी मांग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर है। संगठन ने सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में इस्तेमाल होने वाले ऐसे प्रमाणपत्रों के लिए स्पष्ट नियम बनाने की अपील की है, ताकि पात्र आयुष डॉक्टरों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की मान्यता को लेकर असमंजस न रहे। अलग आयुष संचालनालय और मंत्रालय बनाने की मांग तीसरी और चौथी मांग महाराष्ट्र राज्य में अलग आयुष संचालनालय और पृथक आयुष मंत्रालय के गठन से जुड़ी हैं। संगठन के अनुसार, फिलहाल आयुष क्षेत्र से संबंधित कामकाज अलग-अलग विभागों में बंटा हुआ है। ऐसे में एक स्वतंत्र प्रशासनिक व्यवस्था बनने से नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन में सुविधा हो सकती है। छात्रों को परीक्षा के लिए एक अतिरिक्त मौका देने की अपील पांचवीं मांग आयुष पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों से संबंधित है। संगठन ने पहले वर्ष की परीक्षा पास करने के लिए उपलब्ध चार अवसरों को बढ़ाकर पांच करने की मांग की है। उसका कहना है कि कोरोना काल के दौरान पढ़ाई प्रभावित होने के कारण कुछ विद्यार्थियों को राहत मिलनी चाहिए। डॉ. अमोल अंबेकर के अनुसार, आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टरों को सरकारी योजनाओं में अवसर मिलने से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिल सकती है। उन्होंने योग्यता के आधार पर आयुष डॉक्टरों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल करने की जरूरत बताई।

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे

पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर कोबरा के संदिग्ध जहर की खेप जब्त की है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त सामान की कुल कीमत 5 करोड़ 21 लाख 80 हजार 100 रुपये बताई गई है। गुप्त सूचना के आधार पर तीन आरोपी गिरफ्तार गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर काशीगांव के पास अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फैजान अजीज (30), अब्दुल शेख (51) और मोहम्मद खान (23) के रूप में हुई है। फैजान अजीज नवी मुंबई के तलोजा का निवासी है, जबकि अब्दुल शेख और मोहम्मद खान मानखुर्द के चीता कैंप इलाके में रहते हैं। टीम ने डोडिया पेट्रोल पंप के पास कार्रवाई कर तीनों को पकड़ा। इसके बाद आरोपियों की तलाशी और जब्त सामग्री का पंचनामा किया गया। मामले में आगे की जांच जारी है तलाशी और पंचनामा के दौरान कांच की बोतलों में रखा संदिग्ध सांप का जहर बरामद हुआ। इसकी पहचान कोबरा के जहर के रूप में होने का संदेह है। जब्त जहर का वजन 393 मिलीग्राम बताया गया है। इसके अलावा करीब 80 हजार रुपये की मोटरसाइकिल और तीन मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने तीनों आरोपियों को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों को जहर कहां से मिला, इसकी आपूर्ति किसने की और इसे किसे बेचा जाना था। इस तस्करी के पीछे किसी बड़े गिरोह के सक्रिय होने की भी आशंका जताई जा रही है। मुंबई शहर स्थित वन रेंज कार्यालय में वनरक्षक युवराज जोशी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राहुल कुमार पाटिल के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक सुहास कांबले मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।

IIT बॉम्बे छात्र साहिल वाकोड़े

माता-पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मामले की सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। बेटे को प्रताड़ित करने और धमकाने के लगाए आरोप मृतक छात्र साहिल के माता-पिता ने आईआईटी संस्थान के कुछ फैकल्टी सदस्यों पर प्रताड़ित करने, धमकाने और जाति से जुड़ी टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं। याचिका के मुताबिक, 18 सितंबर को परीक्षा के दौरान साहिल को कथित तौर पर मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया था। इसके बाद उसे परीक्षा हॉल से बाहर निकालकर विभागाध्यक्ष के कार्यालय में करीब एक घंटे तक पूछताछ की गई। माता-पिता का आरोप है कि उसे दोबारा परीक्षा देने या नई उत्तर पुस्तिका नहीं दी गई। साथ ही, निलंबन और संस्थान से निकालने की धमकी देकर उससे माफीनामा लिखवाया गया। साहिल को काउंसलर या मेंटर की मदद भी नहीं दी गई आईआईटी बॉम्बे के छात्र साहिल वाकोड़े माता-पिता ने यह भी आरोप लगाया है कि साहिल ने 13 सितंबर की एक बैठक में प्रोफेसर डुला पर जाति से जुड़ी टिप्पणी करने और झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने की बात बताई थी।। उनका कहना है कि परीक्षा की घटना के बाद साहिल को मानसिक सहारा देने के लिए किसी काउंसलर या मैटर की मदद भी नहीं दी गई। याचिका के अनुसार, परीक्षा की घटना के बाद साहिल हॉस्टल के कमरे में लौट गया और उसी शाम उसकी मौत हो गई। मामले की सही तरीके से पड़ताल नहीं हो रही 19 सितंबर को पवई पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता और एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

बागेश्वर धाम में 51 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह, 9 दिसंबर को होगा भव्य आयोजन

7 दिसंबर से शुरू होंगे मांगलिक कार्यक्रम, जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग के लिए मठ की पहल

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान
भिवंडीः जरूरतमंद परिवारों की कन्याओं के विवाह में सहयोग और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भिवंडी स्थित श्री बागेश्वर धाम सनातन मठ की ओर से 9 दिसंबर 2026 को 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जाएगा। मठ की ओर से पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे इस समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आयोजन की तैयारियों और कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी देने के लिए शनिवार, 31 अक्टूबर को मठ परिसर में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। इस दौरान मठ के प्रबंधक प्रशांत शुक्ला और प्रबंधन समिति के सदस्यों ने बताया कि चार दिवसीय समारोह के तहत 7 दिसंबर को हल्दी एवं भजन कार्यक्रम, 8 दिसंबर को



मेहंदी और संगीत, 9 दिसंबर को विवाह समारोह तथा 10 दिसंबर को सत्यनारायण पूजा एवं नवदंपतियों की विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रबंधन समिति के अनुसार, इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग करना है। धार्मिक एवं सामाजिक सेवा के माध्यम से समाज में आपसी सहयोग, समर्पण और सद्भाव की भावना को मजबूत करना भी इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। आयोजकों ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर सनातनी भाइयों-बहनों और नागरिकों से इस पुनीत कार्य में तन-मन और समर्पण भाव से सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सामूहिक प्रयासों से 51 कन्याओं का विवाह समारोह भव्य और सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होने और इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक परिवार श्री बागेश्वर धाम सनातन मठ, भिवंडी के कार्यालय से संपर्क कर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

डिग्री है, लेकिन अदद नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में आयुष डिग्रीधारियों को भी मिले मौका



महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टरों ने केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव को पत्र लिखकर पृथक आयुष मंत्रालय और NHM में भर्ती समेत 5 प्रमुख मांगें रखी हैं। महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टरों ने केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव को पत्र लिखा। सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं और स्वास्थ्य केंद्रों में काम का अवसर मांगा। अलग आयुष मंत्रालय और परीक्षा के पांच मौके देने की मांग की। महाराष्ट्र के आयुष डॉक्टरों ने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी भागीदारी बढ़ाने की मांग उठाई है। इस संबंध में इंटिग्रेटेड डॉक्टर्स एसोसिएशन (नेशनल) ने केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव को पत्र लिखकर पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ...शेष 7 पर

मुंबई के 3 सरकारी कॉलेजों में बदहाल सुविधाओं पर भड़के छात्र, मंत्री ने दिए समीक्षा के निर्देश

वीजेटीआई, जीएलसी और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुंबई में जर्जर हॉस्टल, पानी की कमी व शिक्षकों की अनुपस्थिति पर छात्रों का विरोध। मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने दिए नए हॉस्टल के निर्देश। मुंबई के तीन सरकारी कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की कमी। वीजेटीआई के हॉस्टल जर्जर, बांद्रा पॉलिटेक्निक में चार साल से पानी संकट। छात्रों की शिकायतों के बाद नए हॉस्टल बनाने को मंजूरी। मुंबई शहर के तीन प्रमुख सरकारी कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाल स्थिति को लेकर छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है। वीरमाता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज और बांद्रा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कहीं जर्जर हॉस्टल, कहीं पानी की



कमी तो कहीं शिक्षकों और पढ़ाई से जुड़ी समस्याएं सामने आई हैं। वीजेटीआई में 22 अक्टूबर को प्रथम वर्ष के डिप्लोमा छात्र की डेंगू से मौत के बाद कॉलेज की साफ-सफाई और स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले सितंबर में छात्रों ने तीन हॉस्टल की खराब हालत को लेकर प्रशासन को पत्र लिखा था। इन हॉस्टलों में करीब 1,200 छात्र रहते हैं। छात्रों का कहना है कि करीब 60 साल पुरानी इमारतों में दरारें हैं और प्लास्टर गिरने का खतरा बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने छात्र और छात्राओं के नए हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बांद्रा के कॉलेज में 4 साल से पानी की कमी वहीं, बांद्रा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पिछले चार साल से पानी की कमी, हॉस्टल की परेशानी और पढ़ाई में देरी की शिकायतें है। छात्रों का आरोप है कि कई विषयों का पाठ्यक्रम अधूरा है और प्रैक्टिकल भी बाकी है। विरोध के बाद कॉलेज में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। खाली शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही गई है। उधर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में छात्रों ने 'सेव जीएलसी' अभियान शुरू किया है। उनकी मांग है कि नियमित शिक्षक नियुक्त किए जाएं, छात्रवृत्ति समय पर मिले और परिसर की मरम्मत ठीक से हो। मंत्री ने दी हॉस्टल बनाने की मंजूरी मुंबई छात्रों ने परीक्षा परिणामों में ...शेष 7 पर

भोईर परिवार को न्याय दिलाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा: सुमित म्हात्रे

शाई गांव में वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई में घर तोड़े जाने का मामला, पीड़ित परिवार से मिलकर प्रशासन को घेरने की दी चेतावनी

सिटी न्यूज़ मुंबई/गनी खान
भिवंडीः मुरबाड तालुका के शाई गांव में वन विभाग और पुलिस की कार्रवाई के दौरान अनंता दत्तू भोईर का घर तोड़े जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के युवा नेता सुमित बाळ्यामामा म्हात्रे ने पीड़ित भोईर परिवार से मुलाकात कर घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने परिवार से पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद साफ कहा कि भोईर परिवार को न्याय दिलाए बिना वह चैन से नहीं बैठेंगे। परिवार का आरोप है कि अनंता भोईर ने अपनी जीवनभर की मेहनत और जमा



पूंजी से परिवार के लिए घर बनाया था। लेकिन शनिवार सुबह करीब आठ बजे टोकावडे वन विभाग और मुरबाड पुलिस ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके घर को जमीनदोज कर दिया। आरोप यह भी है कि कार्रवाई के दौरान परिवार को घर का जरूरी सामान और घरेलू वस्तुएं बाहर निकालने तक का मौका नहीं दिया गया। घटना की जानकारी मिलने पर सुमित म्हात्रे शाई गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग व्यक्ति ने जिंदगीभर मेहनत कर अपने परिवार के लिए आशियाना खड़ा किया था। इस तरह घर को तोड़ा जाना बेहद गंभीर मामला है। संबंधित प्रशासन से इस कार्रवाई को लेकर जवाब मांगा जाएगा। म्हात्रे ने भरोसा दिलाया कि अनंता भोईर और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी।

मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर कोबरा के जहर के साथ 3 गिरफ्तार, 5.21 करोड़ रुपये की खेप जब्त



मीरा-भाईंदर के काशीगांव में पुलिस और वन विभाग ने कोबरा के संदिग्ध जहर की खेप जब्त की। मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और जांच अभी जारी है। कांच की बोतलों में रखा 393 मिलीग्राम संदिग्ध सांप का जहर बरामद। जब्त सामान की कुल कीमत 5.21 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। अदालत ने तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। राष्ट्रीय उद्यान में शिकार की घटना के बीच मीरा- भाईंदर में वन्यजीव तस्करी का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुंबई-अहमदाबाद हाईवे पर काशीगांव स्थित डोडिया पेट्रोल पंप के पास ...शेष 7 पर

यह दैनिक मालक-मुद्रक-प्रकाशक, संपादक मोहम्मद शकील अब्दुल रफीक ने सिटी इन्टरप्राजेस धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे से प्रकाशित किया, मुख्य कार्या लय- धरती कॉम्पलेक्स शॉप नं. 11, एवरशाईन नगर, मिरा रोड (पूर्व), जिल्हा - ठाणे महाराष्ट्र।मुंबई कार्या लय- शॉप नं. 14 उपाध्याय इंडस्ट्रियल इस्टेट, दहिसर चेक नाका, मुंबई इस समाचार पत्र में प्रकाशित सभी समाचारों से संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है किसी भी विवाद का निपटारा मा. ठाणे न्यायालय के अधीन होगा संपादक मो. शकील अ. रफीक : मो. 9869128483
Email : shakeelsahara@gmail.com / citynewsmumbai@gmail.com website : www.citynewsmumbai.in RNI No. : MAHHIN/2012/47486